

approved; 57 applications have been rejected. The increase in industrial production likely to be achieved in consequence of the approvals given will become noticeable only after some time, when the parties have taken the necessary steps to give effect to the approvals so accorded.

Disturbances in Aligarh and Banaras Universities

1471. SHRI RANABAHADUR SINGH:

SHRI M. S. PURTY :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether there have been disturbances recently in the Universities of Aligarh and Banaras, if so, the reasons therefor;

(b) whether there has been loss of property and life; and

(c) if so, the extent thereof and the reaction of Government thereon?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI F. H. MOHSIN): (a) No Sir.

(b) and (c). Do not arise.

Foreign Nationals Overstaying in India

1472. SHRI PAMPAN GOWDA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the number of foreign nationals from various countries who are staying in India by violating the passport rules, State-wise; and

(b) the steps taken by Government in this regard?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI F. H. MOHSIN): (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

मध्यप्रदेश में कम्पनियों की स्थापना के लिए लाइसेंस ।

1473. श्री कंगर चरण दीक्षित : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिन्होंने 1971-72 में मध्य प्रदेश में नई कम्पनियाँ

स्थापित करने के लिये लाइसेंस दिये गये हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस कम्पनियों को वित्तीय सहायता भी दी है; और

(ग) यदि हा, तो कुल कितनी धनराशि सहायता क रूप में दी गई ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जारी किये गये लाइसेंसों/आशयपत्रों के विस्तृत व्यूरे 'दि वीकली बुलेटिन आफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, इम्पोर्ट लाइसेंसिंग एण्ड एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग' दि वीकली इंडियन ट्रेड जर्नल', एण्ड दि मथली 'जर्नल आफ इंडस्ट्री एण्ड ट्रेड' में नियमित रूप से प्रकाशित किये जाते हैं। इन प्रकाशनों की प्रतियाँ समद के पुस्तकालय में भेज दी जाती हैं।

(ख) और (ग) भारत सरकार औद्योगिक उपक्रमों को सीधे कोई वित्तीय सहायता नहीं देती है।

मध्य प्रदेश के जिलों में ग्रामीण औद्योगिक परियोजना

1474. श्री गंगा चरण दीक्षित : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में उन जिलों के क्या नाम हैं जहाँ ग्रामीण औद्योगिक परियोजना कार्यक्रम चलाया जा रहा है;

(ख) उक्त प्रत्येक जिले में आरम्भ किये गये उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों की पूर्ति के संदर्भ में क्या प्रगति हुई है, और

(ग) क्या चालू वर्ष के दौरान जेठ जिलों में भी उक्त कार्यक्रम चालू करने संबंधी किसी प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) केन्द्र द्वारा प्रायोजित ग्रामीण औद्योगिक परियोजनाओं के कार्यक्रम का समाप्ति वर्ष 1962-63

में किया गया था। मध्य प्रदेश के लिये तीन ग्रामीण औद्योगिक परियोजनाएँ दी गई थी यथा, भिण्ड जिले में भिण्ड, अम्बिकापुर जिले में सरगुजा तथा पूर्वी निमाड़ जिले में पूर्व निमाड़। एक और परियोजना वर्ष 1964-65 में दुर्ग जिले के भिलाई स्थान में स्थापित की गई थी। मार्च 1971 तक इन परियोजनाओं में भिण्ड जिले में 3 सामुदायिक विकास खण्ड अम्बिकापुर जिले में 4 सामुदायिक विकास खण्ड, पूर्वी निमाड़ जिले में 6 सामुदायिक विकास खण्ड तथा दुर्ग जिले में 4 सामुदायिक विकास खण्ड सम्मिलित थे। फरवरी, 1 अप्रैल 1971 में 15,000 की जनसंख्या वाले नगरो को छोड़कर इन ग्रामीण औद्योगिक परियोजनाओं के कार्यक्रम का विस्तार मझ जिलों में कर दिया गया है। चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इन परियोजनाओं के लिये शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता मिलती रहेगी।

पाचवी पंचवर्षीय योजना के लिये पाच नई ग्रामीण औद्योगिक परियोजनाओं को स्वीकृत कर दिया गया है। इनके लिये चार जिलो यथा दमोह, सिक्ता, छतरपुर तथा भाबुजा का चुनाव कर लिया गया है परन्तु राज्य सरकार से पाचवी परियोजना के लिए अभी भी प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ है। प्रारम्भिक कार्य जैसे परि- योजना के लिये कमचारियों की नियुक्ति और प्रशिक्षण विस्तृत विकास कार्यक्रम तैयार करने हेतु विस्तृत तकनीकी आधिक सर्वेक्षण का कार्य हाथ में ले लिया गया है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि के अन्त तक इसके पूरे हो जाने की आशा है ताकि पाचवी योजना के आरम्भ में ही कार्यान्वयन का कार्यक्रम प्रारम्भ हो जाये। पाचवी योजना के अन्त तक इन नई परियोजनाओं को शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता मिलती रहेगी।

(ख) वर्तमान चार परियोजनाओं के कार्यक्रम में प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था आम सुविधा केन्द्रों की स्थापना, व्यावसायिक योजनाएँ बनाना, तकनीकी मार्गदर्शन की व्यवस्था, विस्तार सेवाएँ

उपलब्ध कराना, तथा निवेश हेतु औद्योगिक एककों को अभिन्न ऋणों का देना सम्मिलित है। चार वर्तमान परियोजनाओं के औद्योगिक विकास कार्यक्रम के लिये वर्ष 1962-71 की अवधि में मध्य प्रदेश सरकार को 95.98 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता दी गई थी जिसमें 34.41 लाख रुपये अनुदान तथा 61.57 लाख रुपये ऋण के रूप में थे। इन परियोजनाओं की मार्च 1971 तक की विस्तृत वास्तविक उपलब्धिया नीचे दी जाती है।

(1) भिलाई ग्रामीण उद्योग परियोजना:— परियोजना वर्ष 1965 में प्रारम्भ हुई थी। वर्ष 1965-71 की अवधि में विभिन्न योजनाओं पर कुल 12.64 लाख रुपये खर्च हुए। मार्च 1971 तक परियोजना ने 380 औद्योगिक एककों को जिनमें से 130 एकक नये थे, सहायता दी तथा 1800 लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किये गये।

(2) भिण्ड ग्रामीण उद्योग परियोजना:— वर्ष 1962-71 की अवधि में विभिन्न योजनाओं पर कुल 21.20 लाख रुपये खर्च हुये। 1 मार्च 1971 तक परियोजना ने 770 औद्योगिक एककों को जिनमें 518 एकक नये थे, सहायता दी तथा लगभग 1633 लोगों को रोजगार प्रदान किया गया। स्थापित किये गये औद्योगिक एककों में गलीचे (कारपेट) बनाना, निवाड बनाना, बड़ईगरी, लुहारी आदि जैसे उद्योग सम्मिलित हैं। वर्ष 1970-71 के दौरान एककों में 20.23 लाख रुपये का निवेश हुआ। वर्ष 1969-70 में विभिन्न औद्योगिक एककों में जिनमें उत्पादन होने लगा था, कुल 24.25 लाख रुपये के मूल्य का उत्पादन हुआ बताया गया है। परियोजना ने रंगाई छपाई, रस्ते आदि बनाने के प्रशिक्षण केन्द्र भी संगठित किए गए।

(3) पूर्वी निमाड़ ग्रामीण औद्योगिक परियोजना:— वर्ष 1963-71 की अवधि में विभिन्न योजनाओं पर कुल 19.60 लाख रुपये

खर्च हुए। मार्च 1971 तक परियोजना ने 524 औद्योगिक एकको को जिनमें 193 नये एकक थे, वित्तिय अथवा अन्यथा सहायता पहुँचाया जिससे 1482 लोगों को रोजगार मिला। सहायता प्राप्त एकको में से गैस बेल्डिंग पैट्रोमेक्स सुधारने, कटोले तार बल्डिंग, रोलिंग शटर, कृषीय उपकरण आदि बनाने के एकक हैं। वर्ष 1970-71 में इन एकको में 14 07 लाख रुपये का निवेश हुआ। वर्ष 1970-71 के दौरान विभिन्न एकको में कुल 26 00 लाख रुपये मूल्य का उत्पादन बताया जाता है।

(4) सरगुजा ग्रामीण उद्योग परियोजना.— वर्ष 1962—71 को अवधि में कुल 15 15 रुपये खर्च हुए। मार्च 1971 तक परियोजना ने 841 औद्योगिक एकको को जिनमें 515 एकक नये थे, वित्तिय अथवा अन्यथा सहायता दी तथा 2500 लोगों को रोजगार प्रदान किया गया। इस परियोजना में परम्परागत उद्योगों का ही विकास हुआ। फिर भा, चावल तथा आटा मिले, बने बनाए कपड़ विद्युत करघा आदि स्थापित करने के प्रयत्न किये गए। इन केन्द्रों में मार्च 1971 तक 668 कारागार प्रशिक्षित किये गये। जिनमें से 463 प्रशिक्षणाथियों को इन्हीं उद्योगों में खपा लिया गया।

(ग) आगामी 20-25 वर्षों में सरकार ने सारे देश में इस कार्यक्रम को चलाने का निणय किया है। पाचवी पंचवर्षीय योजनाओं को अवधि में उत्तरोत्तर कतिपय नई परियोजनाए हाथ में तब तक दो जाती रहेंगी जब तब मध्य प्रदेश के सारे जिलों में ये स्थापित न हो जाय। सर्व प्रथम राज्य के पिछड़े जिलों में यह कार्यक्रम अपनाया जायेगा। वर्तमान में पाचवी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आने वाले 5 नई परियोजनाओं को छ.डकर और अधिक परियोजनाओं के हाथ में लेने का कोई अन्य प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

Medium Scale Industries in Mysore

1476 SHRI C. K. JAFFER SHARIFF: Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND SCI-

ENCE AND TECHNOLOGY be pleased to state.

(a) the number of medium scale industries alongwith their location in Mysore State and the items manufactured by them,

(b) the total investment on these industries, and

(c) the number of persons employed by them during the last three years?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (SHRI SIDDHESHWAR PRASAD) (a) to (c) Separate statistics are not maintained in respect of medium scale industries. Further, there is no separate classification of Industries into large and medium scale

Invitation to Personalities for TV Programme

1477 SHRI LALJI BHAI Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state the criteria for inviting different personalities to take part in different current affairs programme of Television Centre, New Delhi?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI DHARAM BIR SINHA) The criteria generally adopted are knowledge of the subject fluency of expression and telegenic personality

आकाशवाणी तथा टेलिविजन पर स्वाधीनता की 25 वीं वर्षगांठ सम्वधी कार्यक्रम

1478 श्री लालजी भाई : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आकाशवाणी तथा टेलीविजन पर स्वाधीनता की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर किस प्रकार के विशेष कार्यक्रम प्रसारित किये जायेंगे तथा इन प्रसारणों की अवधि तथा तारीखें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : भारतीय स्वाधीनता की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आकाशवाणी के कार्यक्रमों की योजना समूचे वर्ष के लिये तैयार की जा रही